

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्रीश्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्रीसत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

विकसित राजस्थान की ओर बढ़ते कदम

पेयजल

- ग्रामीण क्षेत्रों में 20 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन
- शहरी क्षेत्र में पेयजल के हेतु अमृत 2.0 योजना में 5 हजार 123 करोड़ रुपये के कार्य
- मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) में 5 हजार 830 करोड़ रुपये के कार्य
- 1000 ट्यूबवेल व 1500 हैंडपंप

राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित PKC-ERCP)

- 9 हजार 416 करोड़ रुपये के कार्यदिश जारी
- 12 हजार 64 करोड़ रुपये की निविदाएँ जारी
- 12 हजार 807 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी
- आगामी वर्ष में लगभग 9 हजार करोड़ रुपये के नवीन कार्यों की शुरुआत
- Rajasthan Water Grid Corporation में लगभग 4 हजार करोड़ रुपये के कार्य

ऊर्जा

- मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वितों के घरों पर निःशुल्क सोलर प्लांट्स लगाकर 150 यूनिट्स बिजली प्रतिमाह निःशुल्क
- 6 हजार 400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य
- 5 हजार 700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के नए कार्यों की शुरुआत

सड़क

- 6 हजार करोड़ रुपये की लागत से 21 हजार किमी. नॉन-पेचेबल सड़कों में सुधार
- 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनेंगे हाईवे, बाईपास, ब्रिज एवं एलिवेटेड रोड
- PMGSY के अंतर्गत 1600 बसावटों को जोड़ा जाएगा
- 5 हजार से अधिक आबादी वाले 250 ग्रामीण कस्बों में अटल प्रगति पथ
- सड़क सुरक्षा के लिए हाइवे पर जीरो एक्सीडेंट जोन व 50 ब्लैक स्मॉट का सुधार कार्य
- 15 शहरों में रिंग-रोड के निर्माण हेतु डीपीआर बनेगी
- हाईवे पर 20 ट्रैमा सेंटर्स के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान, साथ ही 25 Advanced Life Support Ambulances भी उपलब्ध होगी

लाखों युवाओं को सौगात

- आगामी वर्ष में 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्ती
- निजी क्षेत्र में एक लाख 50 हजार युवाओं को रोजगार
- 500 करोड़ रुपये का विवेकानन्द रोजगार सहायता कोष
- 'विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना' में 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान

ग्रामीण विकास

- मनरेगा के अंतर्गत 3 हजार 400 लाख मानव दिवसों का सृजन
- स्वामित्व योजना में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे
- दादूदयाल घुमन्तू सशक्तिकरण योजना में 25 हजार परिवारों को पट्टे
- पंचगौरव योजना को गति देना, 550 करोड़ रुपये का प्रावधान
- एससी/एसटी कल्याण के लिए एससीएसपी एवं टीएसपी फण्ड की राशि बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपये

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना

- 6 हजार वरिष्ठजनों को हवाई मार्ग से तथा 50 हजार को ए.सी. ट्रेन से तीर्थ यात्रा

सामाजिक सुरक्षा

- विभिन्न वर्गों के पात्र को देय पेंशन बढ़ाकर एक हजार 250 रुपये प्रतिमाह
- विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्ध-घुमन्तू समुदायों के लिए 'दादूदयाल घुमन्तू सशक्तिकरण योजना'
- बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए 35 हजार स्कूटी वितरण का लक्ष्य
- खाद्य सुरक्षा हेतु 10 लाख नवीन Units NFSA लाभान्वित के रूप में जोड़ना
- 5 हजार उचित मूल्यों की दुकानों पर अन्नपूर्णा भण्डार

महिला

- 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाये जाने का लक्ष्य
- 3 लाख लखपति दीदियों को आगामी वर्ष में 1.5 प्रतिशत ब्याज दर पर 1 लाख रुपये तक का ऋण
- मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना-आंगनबाड़ी पर सप्ताह में 5 दिवस दूध
- गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना की शुरुआत

नगरीय विकास

- शहरी क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के तहत लगभग 12 हजार 50 करोड़ रुपये के कार्य
- 500 Pink Toilets का निर्माण
- समस्त शहरों में 50 हजार स्टीट लाइट्स
- सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अम्बाबाड़ी एवं विद्याधरनगर (टोडी मोड़ तक) जयपुर मेट्रो का कार्य
- शहरी क्षेत्रों में 500 नई बसें उपलब्ध
- 100 अत्याधुनिक Robotic-Three-One सीवरेज सफाई मशीनें

सुशासन

- प्रथम चरण में 3 हजार से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में अटल ज्ञान केन्द्र
- Ambedkar Institute of Constitutional Studies and Research की स्थापना
- 8 नए जिलों में विभिन्न विभागीय कार्यालयों की स्थापना के लिए एक हजार करोड़ रुपये

हरित बजट

- राज्य का प्रथम हरित बजट (Green Budget)
- Circular Economy के व्यापक प्रसार के लिए Rajasthan Circular Economy Incentive Scheme-2025
- मिशन हरियाळो राजस्थान के अंतर्गत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य
- लघु एवं सीमान्त कृषकों को बैलों से खेती पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष
- 250 करोड़ रुपये राशि की 'हरित अरावली विकास परियोजना'
- स्वयं सहायता समूह की 25 हजार महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षण
- एक लाख लाभार्थियों को निःशुल्क Induction Cook Top-Cooking System वितरण का लक्ष्य

औद्योगिक विकास

- निवेश सुविधा के लिए 'सिंगल विंडो - वन स्टॉप शॉप'
- Service Sector में निवेश हेतु Global Capability Centre (GCC) Policy
- Trading Sector के विकास एवं संवर्द्धन हेतु Rajasthan Trade Promotion Policy
- DMIC (Delhi Mumbai Industrial Corridor) से लिंक कर 2 Logistics Parks

कृषि बजट

- आगामी वर्ष में 35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण का लक्ष्य
- किसान सम्मान निधि की राशि अब 9 हजार रुपये प्रतिवर्ष
- राजस्थान कृषि विकास योजना में 1 हजार 350 करोड़ रुपये
- गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल बोनस राशि बढ़ाकर 150 रुपये
- Micro Irrigation के लिए एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान
- आगामी वर्ष में 3 लाख 50 हजार हेक्टेयर में Drip एवं Sprinkler Irrigation System के लिए अनुदान
- 25 हजार Farm Ponds, 10 हजार डिग्गियों, 50 हजार सौर पम्प संयंत्रों तथा 20 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन के लिए 900 करोड़ रुपये का अनुदान
- आगामी वर्ष 1 लाख हेक्टेयर में ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का छिड़काव पर प्रति हेक्टेयर 2 हजार 500 का अनुदान

पशुपालन एवं डेयरी

- 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' में श्रेणीवार बीमित पशुओं की संख्या दोगुनी
- एक हजार नवीन सहकारी समितियों/दुग्ध संग्रह केन्द्रों की स्थापना
- मिल्क उत्पाद, डेयरी प्लांट की प्रोसेसिंग एवं पशु आहार संयंत्रों के क्षमता वर्धन हेतु 540 करोड़ रुपये
- गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में 2.50 लाख लाभार्थियों की बढ़ोतरी
- गोशालाओं तथा नंदीशालाओं हेतु प्रति पशु देय अनुदान को बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- समस्त जिला चिकित्सालयों में Diabetic Clinics
- गंभीर/असाध्य रोगों के उपचार के लिए Day Care Centres भी समस्त जिला चिकित्सालयों में प्रारम्भ
- प्रदेश को TB मुक्त बनाना, प्रत्येक CHC पर Digital X-ray Machine, TRU-NAAT (ट्रू-नॉट) व CB-NAAT (CB-नॉट) Machine की उपलब्धता
- 'Fit Rajasthan' अभियान, 50 करोड़ रुपये के प्रावधान
- नवीन आयुष नीति, गांवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित कर 11 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि
- निःशुल्क जाँच एवं दवा हेतु 3 हजार 500 करोड़ रुपये का 'MAA कोष' का गठन
- MAA नेत्र वाउचर योजना की शुरुआत
- 70 वर्ष आयु से अधिक के वृद्धजनों को आवश्यकतानुसार घर पर ही निःशुल्क दवा

कार्मिक कल्याण

- समस्त मानदेय कर्मियों के मानदेय में आगामी वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि
- NFSA राशन वितरण का कार्य संभाल रहे Dealers के कमीशन में भी 10 प्रतिशत वृद्धि
- न्यायिक सेवा के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता
- पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी आगामी वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि

